श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, हम राज्यों से बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि किसानों को अच्छा दाम या समर्थन मूल्य या दाम मिलता है, तो जो हमारी तीन योजनाएं हैं, उनका उपयोग करें और खरीदारी करें, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। जितनी भी किसान वेलफेयर की योजनाएं चलाई गई हैं, उनका क्रियान्वयन तेजी से करें, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI RANJIB BISWAL: I am asking about farmer suicide. Does he have any information?

श्री सभापतिः ये farmer suicides पर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंहः सर, मैं वही बता रहा हूं कि farmer suicides तभी करता है, जब उस पर संकट आता है।

SHRI RANJIB BISWAL: I am asking about farmer suicides. Does he have any information?

श्री सभापतिः क्या इस पर कोई information है, हां या नहीं?

SHRI RANJIB BISWAL: Do you have any information about Odisha suicides?

श्री राधा मोहन सिंहः हमारे यहां आत्महत्याएं कितनी हुई, इस बारे में हम गृह मंत्रालय के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से आंकड़े लेते हैं, ...**(व्यवधान)**...

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, I need your protection.

श्री राधा मोहन सिंहः तो हम वहां से आंकड़ें मंगवा कर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा देंगे। ...**(व्यवधान)**...

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, I am talking about insurance and suicides.

श्री सभापतिः आप वह आंकड़ा मंगवा कर इनको दे देंगे। That is an assurance given by the Minister. Now, Question 168. ...*(Interruptions)*... It is an assurance. Please sit down. Question 168.

भागलपुर के रेशम बुनकरों के लिए योजनाएं

*168. **श्रीमती कहकशां परवीन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सिल्क शहर के नाम से विख्यात भागलपुर शहर में रेशम उद्योग की हालत दयनीय हो गयी है और वहां के रेशम बुनकर भुखमरी की स्थिति तक पहुंच गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने भागलपुर शहर के रेशम बुनकरों की स्थिति में सुधार करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भागलपुर क्लस्टर को टसर सिल्क के लिए जाना जाता है। बिहार में टसर सिल्क के उत्पादन में बढ़ोत्तरी 2013-14 में 32 मी.टन की तुलना में 2015-16 में 41 मी. टन दर्शायी गयी है।

सिल्क बुनकरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा भागलपुर में निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की गई हैं:-

(1) वर्ष 2014-15 में 17.15 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भागलपुर मेगा हथकरघा क्लस्टर के विकास के लिए व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना। प्रमुख घटक इस प्रकार है:-

(i) विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए 9.76 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 10 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर परियोजनाएं (भागलपुर जिले में 07 और बांका जिले में 03) स्वीकृत की गई हैं।

(ii) 89.25 लाख रुपये की कुल लागत के साथ भागलपुर में डिजाइन स्टूडियो एवं उत्पाद विकास केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

(iii) 49.95 लाख रुपये की कुल लागत के साथ बांका जिले में डाई हाउस स्वीकृत किया गया है।

(2) यार्न आपूर्ति योजना के तहत 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान (20.02.2017 तक) भागलपुर के हथकरघा बुनकरों को 8.07 करोड़ रुपए मूल्य के 3.99 लाख किलो ग्राम यार्न की आपूर्ति की गई।

(3) रेशम उत्पादन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए कच्चा माल बैंक की टसर उप इकाई (टी.आर.एम.बी.) स्थापित की गई है ताकि टसर कोया के उत्पादकों के लिए स्थानीय बाजार की सहायता प्रदान की जा सके। विगत 3 वर्षों के दौरान टसर कोया के खरीद और बिक्री की मात्रा क्रमशः 113.62 लाख और 117.52 लाख है।

(4) महिला रीलरों के लिए थाई रीलिंग की प्रक्रिया को बदलने के लिए 271 बुनियादी रीलिंग मशीनों और मोटर चलित चरखे का वितरण किया गया है।

Scheme for silk weavers of Bhagalpur

†*168. SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the condition of Silk industry in Bhagalpur city, known as the Silk city, has become pathetic and the silk weavers there are on the verge of starvation;

† Original notice of the question was received in Hindi.

(b) whether Government has chalked out any scheme to improve the condition of silk weavers of Bhagalpur; and

(c) if so, the details thereof along with achievements in this regard during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI AJAY TAMTA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Bhagalpur cluster is famous for Tasar silk. Production of Tasar Silk is showing increase from 32 MTs in 2013-14 to 41 MTs in 2015-16 in Bihar.

Taking into account the felt need of silk weavers, the following have been sanctioned by the Government of India in Bhagalpur:-

(1) Comprehensive Handloom Cluster Development Project for development of Bhagalpur Mega Handloom cluster in 2014-15 with an outlay of ₹ 17.15 crore. Major components are:–

(i) 10 Block level projects (7 in Bhagalpur district and 3 in Banka district) have been sanctioned with total project cost of ₹ 9.76 crore for implementation of various interventions.

(ii) Design Studio & Product Development Centre at Bhagalpur has been sanctioned at a total cost of ₹ 89.25 lakh.

(iii) Dye House in Banka district has been sanctioned at the total cost of ₹ 49.95 lakh.

(2) Under the Yarn Supply Scheme, 3.99 lakh kg yarn worth ₹ 8.07 crore supplied to handloom weavers of Bhagalpur during the period 2014-15 to 2016-17 (till 20.02.2017).

(3) For promotion of sericulture activities, Tasar Sub-Unit of Raw Material Bank (TRMB) has been set up for providing local market support for the producers of tasar cocoons. During last 3 years, quantity of tasar cocoons procured and sold is 113.62 lakh and 117.52 lakh respectively.

(4) 271 Buniyaad Reeling Machines and Motorised Charaka have been distributed to women reelers to replace the practice of thigh reeling.

श्रीमती कहकशां परवीनः सभापति महोदय बहुत-बहुत शुक्रिया। रेशमी शहर भागलपुर की हालत बहुत खराब है। वहाँ के बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं। बुनकर महाजनों से कर्ज़ लेकर कपड़ा तैयार करते हैं। कपड़ा तैयार करने की कीमत ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप अपना सवाल पूछिए।

श्रीमती कहकशां परवीनः जी। उनको इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। वे पूँजी और बाज़ार के अभाव में बदहाली की स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकार ने अक्टूबर, 2016 में सर्वे का काम शुरू करवाया था। मैं जानना चाहती हूं कि उस सर्वे का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर सर्वे का काम पूरा हुआ है और उसके जो नतीजे निकले हैं, उस संदर्भ में यह सरकार उन नतीजों के आधार पर कौन-से कदम उठा रही है, जिससे इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके?

श्री अजय टम्टाः सभापति जी, माननीय सदस्या ने एक विषय उठाया कि बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमने इसके उत्तर में राज्य सरकार द्वारा जानकारी जुटानी चाही थी और राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि उनके पास सिल्क बुनकरों की भुखमरी की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

दूसरा विषय, चूँकि वास्तव में यह सत्य है कि भागलपुर के रेशम की पूरे भारत और पूरे विश्व में बहुत अच्छी छवि बनी रहती है, मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि देश में जो रेशम का काम है, वह मलबरी, टसर, एरी और मूगा के रूप में होता है। भागलपुर में जो उत्पादन होता है, वह टसर का अत्यधिक होता है। वहाँ टसर पर ही काम होता है। उस कार्य को करने के लिए उसका उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको उस उत्पादन की भी एक जानकारी देना चाहता हूँ। यह जिस प्रकार से देश के अंदर है, उसी प्रकार से बिहार और भागलपुर में है। 2013-14 में टसर का जो उत्पादन था, वह पूरे देश में 2619 मीट्रिक टन था। यह उत्पादन बिहार में, भागलपुर में 32 मीट्रिक टन था। मैं आपको इस बार का आंकड़ा दे रहा हूं, बीच में आंकड़े नहीं दे रहा हूं। यह उत्पादन 2015-16 में 41 मीट्रिक टन था।

माननीय सभापति जी, हमारी सरकार द्वारा 2014-15 में हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए भागलपुर मेगा क्लस्टर पर काम हो रहा है। इसके अंतर्गत वहाँ पर 5,084 लूम्स हैं। यह कार्य हमारे द्वारा स्वयं किया गया है। यदि हम लूम में लोगों के रोजगार और उनके उत्थान की बात करें तो इसमें लगभग 10,000 लोगों के रोज़गार की बात है। हमारे द्वारा इसमें 2 करोड़, 38 लाख रुपये दिए जा चुके हैं और रेस्ट एमाउंट, यानी 1 करोड़, 60 लाख रुपये इस मार्च के अंत में दे दिए जाएंगे। यह माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर है। हमने उसमें एक विवरण भी दिया है। यदि आप उसकी डिटेल्स पूछना चाहेंगी, तो मैं उस पर भी बोल सकता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीनः सभापति जी, जो सवाल किया गया था, माननीय मंत्री की ओर से मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला है। इन्होंने किसी सर्वे की बात नहीं बताई है। मेरा सवाल उनके बच्चों से जुड़ा हुआ है। मैं इनसे दूसरा सवाल यह करना चाहती हूं कि जो वहाँ के बुनकर हैं, उन बुनकरों के बच्चों की सेहत और शिक्षा के लिए कौन-कौन से इंतजाम किए हैं? बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा के

लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि अगर सरकार की उनकी भविष्य निधि, पेंशन या बीमे की कोई योजना है तो सरकार उसको बताए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि उनको रियायती दर पर कर्ज़ा देने की इनकी कौन-सी योजना है?

श्री अजय टम्टा: सभापति जी, माननीय सदस्या ने कहा है कि अगर कोई नई गणना करनी है, तो हथकरघा की चौथी गणना अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होगी। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूं। आपने बोला है ...**(व्यवधान)**... हमने बुनकरों के लिए पाँच एम.ओ.यूज. साइन किए हैं। हमने बुनकरों के लिए पिछले दिनों जो एम.ओ.यूज. साइन किए हैं, उनमें दो एजुकेशनल एम.ओ.यूज. हैं, जिनमें उनके लिए बारहवीं तक की शिक्षा के लिए stipend की व्यवस्था है, उनको प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। उनके उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए भी हमारे द्वारा, सरकार द्वारा एम.ओ.यूज. साइन किए गए हैं।

आपने जो बैंक की बात कही है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि बैंक में भी "मुद्रा बैंक" के माध्यम से हमारे वीवर्स के साथ एम.ओ.यूज. साइन किए गए हैं। "मुद्रा बैंक" के माध्यम से उनकी जो लोनिंग होगी, उस पर जो ब्याज लगेगा, उसका 6 प्रतिशत स्वयं भारत सरकार वहन करेगी। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है।

श्री राम नाथ ठाकुर: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की "मुद्रा योजना" के अंतर्गत एक निश्चित अनुपात में बुनकरों को इस योजना का लाभ देने की योजना है?

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, "बुनकर मुद्रा योजना" के तहत हमने औसत प्रति व्यक्ति ऋणाई 23 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। इसके अंतर्गत भारत सरकार प्रति पात्र बुनकर को 10 हजार रुपये स्वीकृत मार्जिन मनी देती है। और जैसा मैंने आपको मुद्रा बैंक का भी बताया कि 6 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण दिया जाता है। इसमें बुनकर को ऋण प्राप्ति के लिए गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अभी तक देश में 20,129 बुनकरों को 3.98 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि सेरिकल्चर सेक्टर में जो टसर सिल्क है, कई राज्यों में ...

श्री सभापति: यह सवाल सिर्फ एक जगह, भागलपुर का है।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम: सर, कई राज्यों में raw material की कमी पड़ रही है। तो हैंडलूम वीवर्स के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या राज्यों में ज्यादा से ज्यादा raw material बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव रखा गया है? और, हैंडलूम सेक्टर में जो आरआर पैकेज है, उसकी जो गाइडलाइन्स हैं, वे कॉम्प्लीकेटेड हैं, जिसके कारण जितने भी पीडब्ल्यूसीएस हैं, वे इसका फायदा उठाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। क्या सरकार ने इन गाइडलाइन्स में कुछ रिलेक्सेशन करने का कोई प्रस्ताव रखा है?

श्री सभापतिः देखिए, यह सवाल भागलपुर पर है।

श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रमः सर, मैंने सिल्क के raw material के लिए सवाल पूछा है।

श्री सभापतिः भागलपुर में? जी, बता दीजिए।

श्री अजय टम्टाः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या ने टसर से संबंधित raw material पर अपना प्रश्न पूछा है। चूंकि मूल प्रश्न भी हमारी मातृ-शक्ति का है और अभी भी आपने ऐसा पूछा है, तो वास्तव में टसर का raw material जो कोकून होता है, उस कोकून को यार्न के रूप में लाते हैं, वह आपके ध्यान में भी होगा, शायद आपके क्षेत्र में भी हो, दूसरे बाकी मेम्बर्स के क्षेत्र में भी हो। हमने इसमें एक बड़ी पहल की है, इसमें एक बुनियादी रीलिंग मशीन करके इंट्रोड्यूस हुई है। इसका माननीय सदस्या, जो मूल प्रश्नकर्ता थीं, उनको भी पता है। यह काम पहले महिलाओं के द्वारा थाई रीलिंग के द्वारा किया जाता था, जो अमानवीय था और इसमें महिलाओं के शोषण और अल्प-आय की वजह से चिंता थी। हमारी माननीया मंत्री जी ने इसका 8 मार्च, 2017 को शुभारंभ किया है और जो raw material, जो कोकून से यार्न बनना है, उसके लिए बुनियाद रीलिंग मशीन करके लॉंच की है। आगामी तीन वर्षों में पूरे देश में दस हजार मशीनें वितरण करने की योजना है, क्योंकि थाई रीलिंग हमने खत्म करनी है। चूंकि आपका प्रश्न raw material पर था, इसीलिए थाई रीलिंग हमने खत्म करनी है। चूंकि आपका प्रश्न raw material पर था, इसीलिए मैं माननीय सदस्या के पहले सवालों का भी जवाब दे देता हूँ, ताकि उनके संज्ञान में आ जाए और वे अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को बताएं कि हमने 25 हजार रीलिंग मशीनें भागलपुर में दे दी हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shrimati Jaya Bachchan. But is your question on this subject?

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Absolutely! माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनवाए। जो आपने पैसे दिए, उसमें से कितना काम पूरा हुआ है और पैसों का कितना इस्तेमाल हुआ? सिर्फ भागलपुर की बात कर रही हूँ। आप इतना बता दीजिए।

श्री अजय टम्टाः सभापित जी, मैं आपको भागलपुर का बताना चाहता हूँ, जैसा आपने भागलपुर का पूछा है। साल 2014-15 में 17.15 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भागलपुर मेगा हथकरघा क्लस्टर के विकास के लिए व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना है, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए 9.76 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप सुन लीजिए।

श्री अजय टम्टाः आप डिटेल पूछ रहे हैं तो मैं डिटेल बता रहा हूँ और भागलपुर की ही डिटेल बता रहा हूँ, माननीय सदस्या जी।

श्रीमती जया बच्चनः मैंने दो शब्द में पूछा है, दो शब्द में ही आप जवाब दे दीजिए, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं, मंत्री जी।

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Jayaji, please. ...*(Interruptions)*... मंत्री जी, आप अपना जवाब खत्म कीजिए।

श्री अजय टम्टा: माननीय सभापति जी, जब आंकड़े पूछेंगे, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। सभापति जी, इसीलिए हमने 89.25 लाख रुपए की लागत से भागलपुर में डिजाइन स्टूडियो और उत्पादन विकास केन्द्र को स्वीकृत किया है और 49.95 लाख रुपए की लागत के साथ बांका जिले में डाई हाउस बनाने का है और मेगा क्लस्टर में 2.38 करोड़ रुपये दिए भी जा चुके हैं। यह मैंने आपको अलग से अवगत कराया है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु यूर्निवसल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का उपयोग किया जाना

169. श्री अमर शंकर साबले : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से चालू वित्तीय वर्ष में दस हजार करोड़ रुपए व्यय करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी थी और इस कोष के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में महाराष्ट्र सहित कुल कितनी ग्राम पंचायतों और ग्रामीण डाकघरों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है; और

(घ) देश में महाराष्ट्र सहित सभी ग्राम पंचायतों और ग्रामीण डाकघरों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ब्रॉडबैंड हाईवे की व्यवस्था करना डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक है। भारतनेट, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की एक परियोजना है। चालू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में से इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए 4617 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हो चुकी है और चालू वित्त वर्ष 2016-17 में अब तक इस राशि का उपयोग किया जा चुका है।

(ख) विगत वित्त वर्ष 2015-16 में भारत नेट के लिए 2415.10 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई थी। दिनांक 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) में कुल 47,924.76 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में प्राप्त धनराशि